PK-DS/2O/3.00

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shri S.R. Balasubramoniyan; not present. Shri Narendra Kumar Swain; not present. Shri C.M. Ramesh; not present. Shri K.T.S. Tulsi.

SHRI K.T.S. TULSI (NOMINATED): Hon. Deputy Chairman, Sir, I thank you for having given me an opportunity for speaking on the Motion of Thanks on the President's Address. While listening to the speech of the hon. President, I was waiting to hear a word of concern or sympathy with regard to the catastrophic impact which demonetisation, the policy of the Government, had in the country. The effect of demonetisation was felt in the areas of employment as well as industry. However, the deafening silence in the Address is a matter of great concern. There was not even a word of condolence to the families of those, over a hundred, who lost their lives while standing in the queues to withdraw money from the ATMs. I just fail to understand as to what would have caused this kind of a catastrophe. It is said that the design of the new notes was finalised on 19th May, 2016. If the design was finalised on 19th May, what prevented the Government from printing the notes? What prevented the Government from recalibrating the ATMs? This is a tragedy in which over a hundred lives were lost, but no one is sorry about the catastrophic effect or even the loss of lives of our

countrymen. There is no assurance of employment to the families of those who died, because the Government does not want to acknowledge the fact that people have died standing in the queues. There is no compensation, there is no assurance of employment and there is nothing in this Address which gives an assurance with regard to the revival of industries which have shut down. The Government promised two crore jobs every year. Instead of providing jobs, what has happened is that millions of jobs have been taken away from the people who were gainfully employed.

According to the Fifth Annual Employment-Unemployment Survey conducted in October, 2016, the unemployment rate was the highest in five years. If unemployment rate was already the highest in five years, then, one can imagine the impact of losing 60,000 further jobs, which have been lost as a direct result of demonetisation policy. The Survey also states that about 77 per cent of the rural households have no regular income and earn a monthly income of less than Rs.10,000/-. This is the Survey which was conducted by the Labour Bureau, which comes under the Labour Ministry. Was the Government unaware of such a distressful situation of employment, at that very moment, when it adopted the demonetisation policy?

(THE VICE-CHAIRMAN, DR. SATYANARAYAN JATIYA, in the Chair)

The economic growth of a nation is decided by the rate of employment in the country. The Address does not, unfortunately, mention as to how the industrial sector has been hit by demonetisation. For example, Ludhiana hosiery industry which provides employment to around 4,00,000 people, and about 70 per cent of its industrial units has shut down.

The Address mentioned Swachh Bharat Abhiyan and claimed that more than three crore toilets had been constructed, but it did not mention how many of these toilets were functional. The National Sample Survey Office revealed that in 2016-17, only 46 per cent of the 95 lakh toilets, which were built, are usable.

(Contd. by PB/2P)

PB-MCM/2P/3.05

SHRI K.T.S. TULSI (CONTD.): Therefore, there cannot be a more classic example of wastage of taxpayers' money than this. This also amounts to a breach of promise and a breach of faith and misleading the country that this was, in fact, to rake out the black money. Black money is not kept in cash. Everybody knew that. In fact, they have turned every Indian into a criminal that if you have cash, your cash is going to be confiscated and you have to stand in the queue and you cannot even withdraw your own money. This kind of a spectacle has not been seen in India after Partition.

The Government claims that the outlay for Railways has been increased. But it does not mention that hundreds of lives have been lost in never-ending accidents of the trains on account of lack of safety on the tracks. I hope that they will not launch a bullet train on these tracks which cannot even take a speed of 60 kilometres.

I wish the Address would have mentioned as to how many *jawans* have been killed in the borders after surgical strikes and how their families are getting along and whether any of them has been either assured a job or been compensated. Failing to mention the sacrifices of our *jawans*, in fact, belittles their martyrdom. I did not find a word of concern as to how farmers are eking out a living when they are not even getting a minimum price for their crops.

All in all, I feel that the Government needs to introspect and examine their failure in the field of industry, agriculture and employment. Thank you.

(Ends)

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में सरकार की एक साल की उपलब्धियों पर ही चर्चा की है। उसमें इतनी योजनाओं की विस्तार से चर्चा की गई है, उससे तो ऐसा लगता है कि हमारा देश बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, परन्तु वैसा नहीं

है। दावों को हकीकत के साथ जोड़ कर भी देखना होगा। अभिभाषण में नोटबंदी की भी बात की गई है। उसमें कहा गया कि नोटबंदी से काला धन, भ्रष्टाचार, जाली करंसी और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने जैसी बुराइयों का अंत होगा और राष्ट्रपति जी ने सरकार के इस कदम की सराहना भी की है, परन्तु ऐसा नहीं है। अब कितना काला धन आएगा, भ्रष्टाचार कम होगा, कब होगा यह तो भविष्य की बात है, क्योंकि "In the long run we are all dead", अर्थशास्त्री केन्स ने ऐसा कहा है।

अब मैं वर्तमान की बात करता हूं। जब मैं वर्तमान की बात करता हूं तो नोटबंदी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। जनता को बहुत तकलीफों को सहन करना पड़ा, लम्बी-लम्बी लाइनों में लगकर उनको बैंकों में अपने नोट जमा कराने पड़े, पैसा निकलवाना पड़ा। इससे देश में लगभग 135 लोगों की जानें चली गईं। हमारे देश के बाद वेनेजुएला में भी नोटबंदी का काम किया गया। परन्तु वहां पर जनता ने सरकार का सहयोग नहीं किया। 72 घंटे में ही वहां की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई, लोग सड़कों पर आ गए, सारी दुकानें लूट ली गईं, जिस कारण सरकार को एक हफ्ते बाद अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। परन्तु हमारी जनता ने ऐसा नहीं किया और सरकार के नोटबंदी के निर्णय को हौसले से स्वीकार करके तकलीफें सहकर भी काम किया।

(2Q/SC पर जारी)

श्री राम कुमार कश्यप (क्रमागत) : इसके बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा और सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन 135 निर्दोष लोगों की जानें चली गयी हैं, सरकार उनके संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके परिवार को रोज़गार देने या उनकी आर्थिक सहायता करने का काम करे। मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि नोटबंदी के समय नोट लेते हुए उनकी जानें चली गयीं, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में हरेक नागरिक का अहम योगदान होता है, चाहे वह गरीब है या अमीर, चाहे कर्मचारी है या व्यापारी। वे लोग, जो मारे गए, वे भी देश के निर्माण में कहीं न कहीं काम कर रहे थे, उनका भी राष्ट्र के निर्माण में योगदान है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उनके परिवारवालों को रोज़गार मुहैया कराया जाए और उनको compensate करने का काम किया जाए।

दूसरा, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया है। सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए चलाया गया। सरकार का यह कदम सराहनीय है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या घटती जा रही है। अगर मैं सन् 2011 की जनगणना का यहां पर उल्लेख करूं तो सन् 2011 में भारत में 1,000 लड़कों के पीछे 943 लड़कियां थे। जो हमारे भारत के समृद्धिशाली प्रदेश हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और यूपी, उनमें तो स्थिति बहुत ही भयानक है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वहां सन् 2011 में 1,000 लड़कों के अनुपात में 879 लड़कियां थीं, पंजाब में 1,000 लड़कों के अनुपात में 895 लड़कियां, दिल्ली, जो बहुत समृद्धिशाली प्रदेश है, यहां 1,000 लड़कों के अनुपात में

868 लड़कियां, गुजरात में 1,000 लड़कों के अनुपात में 919 लड़कियां और उत्तर प्रदेश में 1,000 लड़कों के अनुपात में 912 लड़कियां थीं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे समाज में लड़कों को ज्यादा और लड़कियों को कम तरजीह दी जाती है। इसके अलावा आज हमारे देश में भ्रूण हत्याएं बहुत हो रही हैं। एक समाचार पत्र के अनुसार अब तक देश में तीन मिलियन भ्रूण हत्याएं हो चुकी हैं। उन लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया गया है, उन्हें अपनी मां का मुंह तक नहीं देखने दिया गया। यह बहुत शर्मनाक बात है। इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा। इसमें जनता का भी सहयोग अनिवार्य है और सरकार को भी इसमें बहुत कुछ करना होगा। सर, मैं "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" में एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बेटी को बचाने और पढ़ाने के अलावा उसका सम्मान भी करना होगा इसके लिए इसमें "बेटी बधाओ" भी जोड़ना चाहिए। यह गुजरात का शब्द है, "बधाओ" का मतलब है कि बेटी का मान-सम्मान भी करना होगा और उसे पढ़ाना भी होगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों का मान-सम्मान किया जाए, क्योंकि लड़कियां हमारे लिए लड़कों से कम नहीं हैं।

महोदय, अभी ओलम्पिक गेम्स हुए। वहां पर हमारे देश से 117 खिलाड़ी खेलने के लिए गए। यह बड़ी खुशी की बात है कि वहां पर दो लड़कियों ने ही हमारे देश के मान-सम्मान को आगे बढ़ाया, दो लड़कियां ही हैं जो वहां से मैडल लेकर आयी हैं, इसलिए लड़कियों के लिए कुछ करना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में लाया जाए। जो सजा जघन्य अपराध करने वालों को दी

जाती है, चाहे वह फांसी की सजा हो या उम्र कैद की, वही सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए जो भ्रूण हत्या करता है।

बेटियों के सम्मान के लिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि केन्द्रीय सरकार को भी इसमें पहल करनी होगी। केन्द्र सरकार की तरफ से एक circular जारी कर दिया जाए कि जब कोई महिला या लड़की किसी केन्द्रीय कार्यालय में जाती है तो कर्मचारी या अधिकारी, जो वहां पर उसे मिलते हैं, वे खड़े होकर उसका मान-सम्मान करें और फिर उसके बाद वे सब अपना काम करें।

इसके अतिरिक्त आज जिन परिवारों में लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं, उनके संबंध में मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उन लड़कियों का भी मान-सम्मान करना होगा, उनके लिए भी हमें कोई योजना बनानी होगी। मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे परिवार, जिनमें लड़कियां ही लड़कियां हैं, उन लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में admission के समय और नौकरियों में भी वरीयता मिलनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब ऐसा होगा तो भ्रूण हत्या जैसी बुराइयां दूर हो जाएंगी।

तीसरा, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बहुत अच्छी बात कही गयी कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव इकट्ठे कराए जाएं। मैं इससे सहमत हूं क्योंकि जब बार-बार चुनाव होते हैं तो उसमें बहुत धन खर्च होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, बहुत अधिक संख्या में उनकी वहां पर ड्यूटी लगानी पड़ती है। मैं इसमें केवल इतना कहना चाहता हूं कि इससे जो पैसा बचेगा, उससे हमारे देश को काफी लाभ होगा क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है। हमारे देश में आज भी 40 परसेंट जनसंख्या

गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। यहां पर बेरोज़गारी की समस्या है। आज पीएचडी किए हुए लड़के-लड़कियां आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट पर लगने के लिए तैयार हैं, इसलिए चुनाव एक साथ हों - यह एक अच्छा कदम है। मेरा सुझाव है कि सभी पार्टियों को विश्वास में लेकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।

(2आर-जीएस पर जारी)

KSK/GS/3.15/2R

श्री राम कुमार कश्यप (क्रमागत): इससे जो पैसा बचेगा, उस पैसे को गरीबी दूर करने के कार्यक्रम में लगाया जाए या बेरोजगारी को दूर करने के कार्यक्रम में लगाया जाए। आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत भयानक रूप ले चुकी है। इसलिए मैं कहूंगा कि उस पैसे से हरेक स्टेट में या हरेक जिले में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगायी जाएं। जब देश में इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, तो उनसे रोजगार बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी, ऐसा मेरा मानना है।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के बारे में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज हमारे किसान बहुत दुखी हैं। हमारे किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए किसान बहुत पीछे चले गए हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसानों को बचाना है, तो सरकार को किसानों के कर्जे माफ करने होंगे। अंत में, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद करता हूं, जय हिन्द, जय भारत।

(समाप्त)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (TAMIL NADU): Mr. Vice-Chairman, Sir, while thanking His Excellency for addressing the Joint Session of this Parliament, on behalf of the DMK, I want to register certain points.

Sir, my first assessment of this Address is that it has made many mountains out of the molehills. All small things have been exaggerated to big things. As a first case, I can quote from the Address, "Financial inclusion is key to poverty alleviation. So, 26 crore plus Jan Dhan accounts have been opened for the unbanked." Sir, opening bank accounts will only add the names of these people in the bank ledgers. It cannot be termed as financial inclusion. Financial inclusion means they should have the finance to operate their accounts. At least, 40 to 45 per cent of these accounts are dormant or inoperative. So, merely opening accounts in a bank does not mean that it is financial inclusion; it is only inclusion of their names in the bank ledgers. Beyond that, there is nothing that they can claim.

Secondly, Sir, I want to quote the recent report by Oxfam on the economic inequality in India. The Report says, "Fifty-seven millionaires in India possess as much wealth as is possessed by the poorest 70 per cent of the country." The wealth of the 70 per cent of the poor is equivalent to just 57 citizens in India. The Report further says that the Government lost tax and valuable income with the super-rich depositing their wealth in tax havens abroad and manipulating political systems to do so without repercussion. This observation was found in the Oxfam Report. All I want to say is that the Government must promise to bring back the black money

invested in foreign countries. Since they could not do so, they want to show off; they want to present a picture that this Government is against black money and they have taken up this demonetization exercise. I can say, Sir, that out of the total population of this country, 69 per cent people are agriculturists. We know that agricultural income does not attract Income Tax. About 6 to 7 per cent people are fishermen. We know that fishing income does not attract Income Tax. Remaining 15 to 16 per cent are monthly salaried classes. In that also, seven per cent people have paid tax. The remaining people, whose income does not fall under the threshold of taxation, that is, it is less than Rs.3 lakhs, will also not pay tax. Only 7 to 8 per cent of population of India hold heavy money. We have a proverb in Tamil**,** ***"'Mootaipoochikku bayandhundu veettai koluthardhu."*** This means, 'burning the house to kill the bed bugs'. That is what this Government has done. They have burnt the house to kill the bed bugs. Beyond that, there is no fruitful purpose of this exercise. This is only to hide the Government's failure in bringing back the black money from overseas to India. It was the promise made during the elections and the Prime Minister had assured that this was his prime priority.

(Contd. by 2S - GSP)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CONTD.): Sir, there are many other things. I come to Swachh Bharat Cess. The local bodies are directly involved in the cleanliness of the cities. I do not know how much of the cess collected by the Government of India as Swachh Bharat Cess is given to the local bodies.

Sir, there is one issue about the simultaneous elections. It is a serious issue, which is being discussed on various fora. First thing is that simultaneous election is possible only in a two-party democracy. We are a multi-party democracy. Secondly, if we are following First Past the Post system in declaring a candidate as elected, if it is proportional representation, then also, simultaneous election is possible.

Sir, in 1996, we had parliamentary elections; in 1998, once again, we had parliamentary elections; and, in 1999, again, we had parliamentary elections. When the Parliament is dissolved, can we dissolve all the assemblies and conduct simultaneous elections? It is not possible. The system has to change. You must have, at least, proportional representation in election so that simultaneous elections can be possible.

I would like to appreciate certain things in the President's Address because they have followed the steps which our party leader Dr. Kalaignar took when he was the Chief Minister of Tamil Nadu. In 1974 itself, Tamil Nadu had 100 per cent rural electrification. Women Self-Help Groups were

formed in the year 1989 when our leader was the Chief Minister of Tamil Nadu. Slum Clearance Boards and Group Housing Schemes were started. Subsequently, the Group Housing scheme which was started in Tamil Nadu was followed up by the Government of India and was called *Indira Awas Yojana* . It was appreciated by Dr. Jayaprakash Narayana himself.

Sir, we gave free gas connections to the rural poor in the year 1996. Some of the things, which we did in Tamil Nadu long back when the DMK was in power, appear in this President's Address. It is a welcome measure. Otherwise, this Address can be termed as 'making mountain out of molehills'. With these words, I conclude.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, Shri K.C. Ramamurthy.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (KARNATAKA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity, privilege and honour to make my maiden speech on the Motion of Thanks on the President's Address. Before I proceed further, I would like to express my deep sense of gratitude to my party President Shrimati Sonia Gandhi ji, party Vice-President, Shri Rahul Gandhi ji and other senior leaders of the party at the Centre and the State. I also take this opportunity to seek guidance and help from the senior leaders

of not only my party but of the entire House in discharging my duties in my journey as a Member in this House.

Now, the primary objective behind the Address of the hon. President to both the Houses of Parliament is to present the vision of the Government for the forthcoming years. But this year's Address appears to be trumpeting the schemes, programmes and day-to-day working of the Government rather than giving details as to what the Government is going to do in the coming years. Sir, I feel that the Address is monotonous, visionless, insipid and no less than run of the mill. Nothing is mentioned about internal security and the problems of the police personnel. Many of the hon. Members have spoken at length on various aspects. I do not wish to repeat that.

(Contd.by SK/2T)

SK/2T/3.25

SHRI K.C. RAMAMURTHY (CONTD.): With your kind permission, Sir, I wish to concentrate only on a very important and dearer subject to me, the police reforms, which is not only sensitive and important but also having far-reaching consequences. Sir, I would like to mention here that our hon. Prime Minister, while addressing the Director Generals of Police in Guwahati

in 2014, envisaged the concept of SMART police. The hon. Prime Minister had given a unique definition to police which would be strict and sensitive for 'S', modern and mobile for 'M', alert and accountable for 'A', reliable and responsible for 'R' and techno-savvy and trained for 'T'. Since then, the entire country, the entire police force has been looking for transformational change, and it has been more than two years but the SMART police remains only on paper and reduced to a *jumla*. So, I wish that the Government of India, instead of giving slogans, should do something concrete in the area of police reforms. Sir, when we talk of police reforms, I would like to mention here that without proper and effective internal security, progress of the state is not possible. There can be a situation where a serious lawlessness can prevail in the country if police reforms are not taken up in a very, very serious manner. Sir, I have mentioned about police reforms. The police is put to scrutiny every minute by everyone. It can be all of us politicians, it can be establishments; everyone wants to put the police to test. They like to point finger at the police for all the misdeeds committed by so many people. All that is pointed towards the police and the police is held accountable everywhere. But, unfortunately, when it comes to reforming the police and making them strong and effective, no action, as such, has been taken by anybody. Sir, when it comes to reforms, I would like to concentrate on two

aspects -- one is manpower reforms and the other is police station reforms or functioning of the police reforms. When it comes to manpower reforms, I would like to say about the wages that the police get, in *Kannada* they call it *Kanishtha Bille*. I hope my friends here from Karnataka will understand. *Kanishtha Bille* is the least amount. The police get the least salary that a Government servant gets. That was the situation. Of course, in Karnataka, the situation has improved a lot and the police are treated at par with other Government servants. But what I want to mention here, Sir, is that the wages to the police force, wages to the policemen, wages to the police system should not be clubbed with any other Government department. The situation is different; the work function is different; the activities are different. So, they must be on a different level. Their wages should be totally based on the risk factor, based on the efforts that they put in and based on the other activities which they are supposed to perform. Sir, they don't have bargaining power. They are a disciplined force. They cannot even walk to *Jantar Mantar* raising their demands. Never can they do it; never have they done it. They are helpless. Ninety-two per cent of the police force comprises head constables, constables and assistant sub-inspectors. Sir, they are voiceless. Who is to take care of them? It is the Government who should look at it. Both the State and the Central Governments should look

into this issue very, very seriously. If they are not taken care of, if they are not looked after, if they are not taken into confidence, how can they discharge their duties? What efficiency can we expect from them? Sir, the recruitment process is very bad. I am talking this out of my personal experience. Sir, at a given point of time, there are 25 to 30 per cent vacancies in the police force. 25 to 30 per cent vacancies, and everybody expects, the public expects, the Government expects, police to be very, very efficient, honest and all that. But, how can they discharge their duty, how is it possible with 25 per cent vacancies in the police force? With the 25 to 30 per cent police posts which are vacant, they are not able to allot duties properly, they are not able to get leave, they are not able to get their weekly offs, they are not able to enjoy even a single day with their families. All of us here celebrate our festivals.

(Contd. by YSR/2U)

-SK/YSR-LT/3.30/2U

SHRI K.C. RAMAMURTHY (CONTD.): When all of us celebrate festivals and other ceremonies, police are there to give us protection. They are not able to go to their homes to celebrate festivals with their family members. This is the utmost sacrifice that anybody can make. The police are doing

this. And what are we doing for them? What are we thinking about them? Absolutely nothing.

I would like to mention it here that once a policeman is recruited, he never gets trained again. Not many States have a system of training policemen often or equipping them with the knowledge of latest laws or new weaponry. In the current situation, we see a policeman with a *lathi*. That is the maximum that he gets. He is the person who is supposed to face terrorists. He is the person who is supposed to face naxals. He is the person who is supposed to face anti-national elements. He is the person who is held responsible for anything that happens in the police station. And what is it that we are doing for them? Sir, there is nothing that we are doing for them. I would like to mention here that hardly any training is given to a policeman again after he is recruited. The Central Government must think of a system to give them training just like the IPS Officers go for refresher courses at every level whether middle or higher. At every level, we have programmes. We go and interact with other officers and people in the entire country and understand a lot of things. A police constable or a head constable or an ASI or SI or an Inspector hardly gets any training again after joining the service. They are finished. Whatever they learned in the Police

Training Schools or Police Training Colleges, that's the end of it. They don't have any training facilities later.

One very important aspect, which I would like to mention, is about their housing. Police constables or head constables in urban areas particularly do not get private houses. Private housing is not possible for them. A policeman is the least preferred person when it comes to getting a house on rent. There are only 5.8 lakh houses as against the requirement of 17.3 lakh houses. Where should the remaining policemen go? People do not give them their house on rent. They are not recognised. They are socially unacceptable. They have to live in slums. I have personal knowledge of it. They travel from far-off places, from slum areas, to perform their duty in the city and go back in uniform to their houses in the evening. This is the situation. Their housing should be given a priority. It is very unfortunate that this Government, or any Government for that matter, has not taken police reforms very seriously. Nothing about it has been mentioned in the President's Address or in the Budget. The allocation for police itself is very, very poor. It is insufficient.

When it comes to police station, we have seen a lot of buildings, which house them, have been attacked and policemen have been killed in the police stations. Police are robbed of their weapons in the police station.

What about the safety of the police stations? How had these buildings been constructed? In most of the places, the buildings are very, very small. Some of them are like huts. These buildings are not safe. A police station is a place where when public goes, it should feel as if they have gone to a place where they can get justice. There is no place for them to sit. There is no furniture. There are no facilities at all. The policemen, who don't have their own houses, stay in the police station. That becomes a resting place for them. We need to concentrate on this aspect very seriously. The equipment there is outdated.

Sir, all of us are aware that the criminals are now having fast-moving vehicles. They have got the best of weapons. They have got most modern gadgets with them to deal with other criminals. But what is it that the policemen are having in police stations? Absolutely nothing. Can we be confident of the internal security of our country if we don't strengthen the hands of police? If you don't take this matter seriously, will we be able to safeguard our internal security? Sir, I feel the danger to it. The danger is not away from us. It is near us. Unless we take up police reforms very seriously, our internal security may collapse any time. I have mentioned about weapons and latest gadgets.

Now, I come to police welfare measures.

(Contd. by VKK/2W)

-YSR/VKK/2W/3.35

SHRI K.C. RAMAMURTHY (CONTD.): Sir, there is one very sad thing. We have a benevolent fund. It must be there in all the States. Sir, who contributes to the benevolent fund? Policemen themselves will have to contribute for their own benevolent fund. Nobody is there to take care of them. Every policeman will have to contribute Rs.25; a Head Constable contributes Rs.50; an Assistant Sub Inspector contributes Rs.100 and like that, every month, they will have to contribute. Out of that, their welfare activities take place. Is this what we are doing for police welfare? Is this what we are trying to do for them? There is absolutely nothing that we are doing. Police tries to do some cultural programmes and benefit shows and collect some money and through that, they try to educate their children, make a benevolent fund and try to get some medical assistance. This is all that we are doing. It is totally insufficient and it is very bad.

Sir, as I mentioned, the wages for policemen need to be fixed separately. They need not be compared with other Government servants when wages are fixed. Risk factor, weekly offs, holidays, etc. need to be taken into account. Sir, anywhere else, the human rights would have come into effect. We need to see the way the police people are treated and the

way the police stations are functioning. If the same situation existed in any other place, human rights violation would have come into the picture long back. People would have been prosecuted for doing these things. But, there is no voice for the policemen. They are suffering. I would like this House to take note of these problems of policemen and see that some activities, which help the police to improve their morale and improve their economic conditions, are taken up.

Sir, I would like to mention here that from 1961, thirty thousand policemen have lost their lives in performing their duties. I have the greatest respect for the Armed Forces. I am not comparing them in any manner. But, a number of policemen have died in the line of duty. As our friends were mentioning, are the people who died, while standing in queues, not human beings? The same treatment is given to police. These 30,000 people have died and the number is increasing every year. We have the Police Commemoration Day on 21st October. Sir, who attends that function? It is only retired police officers. Public is not concerned about it. There is still that colonial attitude and colonial thinking about police stations and policemen. It is still very deeply rooted in the mindset of our people. That should change. Sir, I feel – I do not know why it has not been done so far – policemen who die on duty should be treated as martyrs. Why are they

not treated as martyrs? They have lost best of their lives, they have sacrificed so much and they died on duty. Why should not they be treated as martyrs? I think we should treat the policemen who die on duty as martyrs. Supreme sacrifice of police goes unnoticed due to indifference shown by polity, media, society and other established institutions. Sir, if the society does not recognise them, if the society does not take care of them, if the Government does not take care of them and if we do not take police reforms seriously and see that something is done, then, serious impact will be there in the society and its impact on serving policemen will be too much. (Time-bell) Sir, this is my maiden speech. I thought I would get some more time.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Fifteen minutes are over.

SHRI K.C. RAMAMURTHY: Sir, please give me five more minutes. Sir, I would like to briefly mention about public-police relationship. The mindset of the public needs to change. It is not that it will change just like that. But, efforts towards that have to be made by various agencies. There is nothing anywhere in the entire Budget Speech or in the Presidential Address. Nothing is spoken about these very, very important aspects which will have

a detrimental effect on the society. If the internal security is proper and if the internal security is strong, the economic development will take place and the society will be peaceful. If that is not there, nothing can be done and nobody can save the country. It will become very, very difficult and impossible.

(Contd. by BHS/2X)

-VKK/BHS-AKG/2X/3.40

SHRI K.C. RAMAMURTHY (CONTD.): Sir, I would like to mention in conclusion that I want this House to ponder over and think of those policemen and officers who stay away from their near and dear ones on all important festivals, on all important celebrations only to ensure that all of us happily celebrate them. I would like this House and the society to think of those policemen and officers, who face criminals, anti-social elements, terrorists, naxals, either unarmed or ineffectively armed or less in numbers. They will not hesitate to go and face them. They will not hesitate to get injured or get killed. They are doing their duty.

I would like this august House to see that the message of the police wellness is well-taken and spread and not use police for political ends, not use police for personal ends. That will not serve any purpose. Unless we take care of our policemen, they will not be able to take care of the country.

All that they require is public acknowledgement of their work, of their sacrifice and suffering. They need to be encouraged. For them to do better, we should stop using police for all personal gains. This, I think, should start from this House. It should become the primary duty and priority of the Central and State Governments to properly take care of most important so-called strong arm of the Government. If the strong arm, for example, becomes weak, useless and ineffective, the outcome is left to the imagination of the House.

There is a strong feeling that police are very corrupt. I do not deny the fact that there are black sheep in police also just like in any other department. But, I feel, 90 per cent of the police force are sincere and hardworking. 10 per cent black sheep are there and because of the 10 per cent the entire Department cannot be painted red. Because of the 10 per cent they cannot say that police are bad, that it is because of the 10 per cent, police reforms cannot take place. It is the duty of the Government to identify the black sheep, to take action against them, improving the 90 per cent to 95 per cent or 98 per cent. That action should be taken. It is like any other department and it is more visible.

Suppose I am walking in Connaught Place. Even if some hundred rupees skip from the pocket of a policeman in uniform and falls down and if

he picks it up, a hundred people will watch and think that somebody has given money and he is picking up. This is the mindset of the people. That should change, Sir. I wish that 90 per cent who are good in the police are recognised, respected and taken care of. Thank you very much for the opportunity given to me, Sir.

(Ends)

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, एक मिनट। यहाँ कोई ऐसा नहीं लग रहा, जो हम लोगों के points को लिख रहा हो। यहाँ ऐसा लगता है कि कोई serious नहीं है। हमने नहीं देखा कि लोग बोल रहे हैं और कोई लिख रहा है, तो प्रधान मंत्री जी हमारे points का क्या जवाब देंगे? यहाँ पर कोई भी नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : मिनिस्टर साहब यहाँ हैं।

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU PUSAPATI): There is attendance here, Sir. …(Interruptions)…

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Yes. It is visible. सभी दिखाई दे रहे हैं। महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया।

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करते हुए भारत के आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा एक सशक्त भारत के निर्माण की दिशा और दशा के सम्बन्ध में उठाए गए क्रांतिकारी कदमों की जानकारी हमें दी, जिसमें किसानों, महिला, युवा वर्ग और गरीबों के लिए जो

योजनाएँ रखी गईं, वे बहुत ही उत्साहवर्द्धक हैं और अत्यंत ही सराहनीय हैं, क्योंकि इसमें 'सबका साथ और सबका विकास' को मूल मंत्र बना कर इसको सकारात्मक ढंग से सार्थक करने का प्रयास दिख रहा है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वैसे तो अनेक दिशाओं से सभी क्षेत्र के विभागों में बहुत ही सराहनीय एवं विकासशील बातें आई हैं, मगर मैं सभी बातों के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित एवं श्रमिक वर्ग से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उन विषयों के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर उस संदर्भ में बात करना चाहता हूँ।

(2वाई/एससीएच पर जारी)

SCH-RL/3.45/2Y

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (क्रमागत) : सर, वर्ष 2016-17 के बजट के आवंटन की तुलना में इस साल के बजट में 35% की बढ़ोतरी की गई है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए 2016-17 में 38,833 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे बढ़ा कर इस साल के बजट में 52,393 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत आभार प्रकट करता हूं।

सर, महामहिम जी के अभिभाषण पर बोलते हुए इस सदन के कुछ सदस्यों ने अपनी बातें रखी थीं, जिनमें खास तौर से आदरणीय शरद जी और आदरणीय सीताराम जी ने कहा कि दलितों, वंचितों और पिछड़ों के लिए इस अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं है।

सर, मैं सदन के सामने इस संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं। आज़ादी के 70 साल के बाद पहली बार इस देश को एक ऐसा प्रधान मंत्री मिला, जिसने यह कहा कि

मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। प्रधान मंत्री ने आदरणीय पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती के उपलक्ष्य में इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की गई है। सर, पिछले अढ़ाई साल में पहली बार इस प्रकार के काम किए गए हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली इस सरकार ने दलितों एवं पिछड़े वर्गों के लिए कई योजनाएं रखी हैं। दलितों के मसीहा और पूरे विश्व के रत्न गिने जाने वाले आदरणीय बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जन्म जयन्ती के उपलक्ष्य में पहले भी बहुत कुछ कहा जाता रहा है, लेकिन पिछले अढ़ाई साल में जो हुआ है, उसका मैं यहां कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा भूमि लन्दन में 10 किंग हेनरीज़ रोड की इमारत को खरीदा गया और वहां पर भव्य स्मारक बनाने की बात रखी गई। कांग्रेस के शासन काल में भी उस इमारत को बेचने का समाचार निकला था, परन्तु कांग्रेस ने इसको खरीदने का कोई भी प्रयास नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको खरीद कर वहां एक भव्य स्मारक बनाने की बात की है। वहां स्मारक बनने के बाद, पढ़ाई के लिए भारत से लन्दन जाने वाले पिछड़े वर्ग के जितने छात्र हैं, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उनके लिए आवास और बुनियादी सुविधाएं दिए जाने का बंदोबस्त ने किया है।

दूसरा, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जन्मशती के उपलक्ष्य में उनके परिनिर्वाण दिवस पर 125 रुपये एवं 10 रुपये के सिक्के जारी किए गए। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी ने नाम से डाक टिकट जारी किया गया, साथ ही दिल्ली के 15 जनपथ पर स्थित, डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान का शिलान्यास आदरणीय प्रधान मंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी जी ने खुद किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन केन्द्र बनाए जाने हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान करके हमने बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास किया है।

महोदय, अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो महाराष्ट्र के दादर में स्थित उनकी चैत्य भूमि को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र के ही चिंचौली, नागपुर को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। गुजरात में, जहां से मैं आता हूं और जहां डा. भीमराव अम्बेडकर जी को बड़ौदा के नरेश, महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़ जी ने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाई के लिए भेजा। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, लेकिन तभी उनको कुछ अनुभव प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर उनके मन में यह संकल्प पैदा हुआ कि मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा। उस समय उन्होंने, बड़ौदा शहर में एक पेड़ के नीचे बैठ करके समाज के उद्धार के लिए संकल्प लिया था, लेकिन आज तक किसी ने उस पेड़ की कोई चिंता नहीं की थी। आज उस संकल्प भूमि पर, जहां डा. भीमराव अम्बेडकर जी के मन में दलितों के उत्थान के लिए संकल्प उभरा था, उनकी 125वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में, बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के नाम से गुजरात की सरकार ने 125 करोड़ रुपये का प्रावधान करके एक बड़ा स्मारक बनाने का संकल्प लिया है।

तीसरा, मैं आपको आगे और भी बताना चाहूंगा। दिल्ली के 26, अलीपुर रोड पर स्थित उनकी परिनिर्वाण भूमि पर, 100 करोड़ की लागत से, संविधान के आकार वाली एक बहुत बड़ी इमारत बनाकर देश की जनता को समर्पित की जाएगी।

(2z/rpm पर जारी)

RPM-DC/2Z/3.50

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (क्रमागत): सर, यहां इस विषय पर भाषणों के दौरान कहा गया कि देश में दलितों के लिए कुछ नहीं किया गया है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं यहां दलितों के बारे में जितनी बातें गिनाऊं, वे कम लगती हैं। मैं यदि इस बारे में पूरा संदर्भ लेकर बातें कहूं तो बहुत समय लग जाएगा।

महोदय, संविधान दिवस पर, पहली बार डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से सदन में दो दिवस की चर्चा रखी गई और उसमें आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि डा. भीमरावराम जी अम्बेडकर के नाम से हमने 'पंच-तीर्थ' का निर्माण किया है। मैंने अभी जिन चीजों का नाम लिया जैसे - शिक्षा भूमि लंदन, चैत्य भूमि, संकल्प भूमि, परिनिर्वाण भूमि आदि के लिए सरकार की ओर से पहली बार किसी के लिए 100 करोड़ रुपए, किसी के लिए 125 करोड़ और किसी के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर के और उनके नाम से स्मारक बनाकर सही रूप से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्री नरेन्द्र जी भाई की सरकार ने किया है।

सर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कमजोर वर्गों पर एट्रोसिटीज़ रोकने के लिए एट्रोसिटीज़ एक्ट पास करके कई प्रावधान किए गए हैं, जिससे उनके ऊपर अत्याचार रुकेंगे। यहां हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आदरणीय मंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने एक्ट में संशोधन करने का बिल पार्लियामेंट से पास कराया,

ताकि दलितों के ऊपर एट्रोसिटीज़ का जो एक्ट है, उसमें खास और कड़े बंदोबस्त किए जा सकें और उनका परिपालन भी हो सके, ताकि उनके ऊपर अत्याचार न हो सकें।

महोदय, मैं दूसरी बात कहूंगा कि देश में कई राज्यपाल बनाए गए, लेकिन एससी वर्ग से कभी राज्यपाल नहीं बनाए गए, लेकिन इस सरकार ने पहली बार आदरणीय राम नाथ कोविंद जी को राज्यपाल के रूप में बिहार भेजा। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी दलित को राज्यपाल बनाया गया।

महोदय, दूसरी अनेक बातें हैं, जिन्हें मैं बताऊंगा। 'मुद्रा बैंक' के माध्यम से गरीबों और छोटे उद्यमियों को 15 लाख रुपए ऋण के रूप में देने की व्यवस्था की गई है। ...(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश: सर, इससे पहले श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी भी राज्यपाल रह चुके हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): ठीक है। श्री शम्भुप्रसादजी, आप अपना भाषण जारी रखिए।

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: सर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी नोटबन्दी का विषय चल रहा था। कैशलेस करेंसी की बातें हो रही हैं, तो उसमें भी 'भीम ऐप' के माध्यम से डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम को पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। 'भारत इंटरफेस फॉर मनी' नाम की मोबाइल ऐप लॉंच कराई गई है। ये बातें दलितों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बातें हैं, जो पहले कभी नहीं हुई थीं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये सब बातें देश में हो रही हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय पं. दीन दयाल जी उपाध्याय की जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में इस वर्ष को 'गरीब कल्याण वर्ष' के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी हुई है। हमारी पार्टी के स्थापक एवं वरिष्ठ नेता गण, जिन के विचारों में 'अन्त्योदय' की बात आई थी और उन्होंने 'अन्त्योदय', यानी जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए काम करने के संकल्प के साथ काम करने की नींव रखी थी, आज उसे आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हम चरितार्थ होता हुआ देख रहे हैं।

महोदय, गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सी बातें यहां कही गईं। 26 करोड़ से अधिक लोगों के 'जन-धन' खाते खोलकर लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से पहली बार जोड़ा गया है और पहली बार अब कैशलेस व्यवस्था से गरीब लोग जुड़ रहे हैं। जिस गरीब ने कभी बैंक देखा नहीं था, जो कभी बैंक नहीं गया था, वह व्यक्ति आज कार्ड लेकर घूम रहा है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने तो एक साल पहले ही कह दिया था कि जन-धन के खाते खुलवाओ, ताकि यह हो सके।

महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग किस प्रकार से सोच रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं यदि कैशलेस व्यवस्था होगी, तो जिस छोटे मजदूर को 10,000 या 15,000 हजार रुपए की पगार पर रखा जाता है और उसे हकीकत में केवल 5000 रुपए देकर चलता कर देते थे, लेकिन अब कैशलेस व्यवस्था में उसके एकाउंट में फैक्ट्री वालों को उसका पूरा वेतन जमा कराना होगा। इस प्रकार उस गरीब को जो पगार मिलती है, वह बैंक टू बैंक जाएगी। उसमें कभी घपला नहीं होगा। हमने अनेक फैक्ट्रियों में ऐसा देखा है कि मजदूर को कैश में पूरा वेतन नहीं दिया जाता है और बाकी वेतन कंपनी के लोग खा जाते हैं। इस समय, आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की

सरकार ने जो कैशलेस की व्यवस्था की है, जिसमें एटीएम टू एटीएम, बैंक टू बैंक या खाते से खाते में कैश ट्रांसफर किया जाएगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो मजदूर, जो छोटे कर्मी काम करते हैं, उन्हें उनका पूरा वेतन मिलने का अवसर प्राप्त होगा

(3ए/पीएसवी पर जारी)

PSV-KR/3A/3.55

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (क्रमागत): तो मैं यह कह रहा हूँ ...(समय की घंटी)... कि ये सभी जो बातें हैं, यहाँ पर प्रत्येक वक्ता ने कही हैं। आदरणीय शरद जी तो यह कह रहे थे कि दलितों का कहीं पर उल्लेख ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि 'उज्ज्वला योजना' दलित-पीड़ित महिलाओं के लिए है। 'जन-धन योजना', 'अटल पेंशन योजना' आदि किनके लिए हैं? ये सभी योजनाएँ उनके लिए हैं, जो छोटे लोग हैं, समाज के अंतिम छोर पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं।

अपनी बात खत्म करने से पहले, मैं अंत में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं परसों भरूच जिले के एक गाँव में गया था। आदरणीय अहमद भाई अभी नहीं हैं। अगर वे होते, तो कहते कि वे उस गाँव को पहचानते हैं। जम्बुसर तहसील का कावली नामक एक गाँव है। वहाँ मैं गया था। मैं जैसे ही यहाँ से गया, तो पूरा गाँव ऐसे उमड़ पड़ा जैसे कि मेरे स्वागत के लिए आया हो। वे मेरा स्वागत करने नहीं आए थे, वे तो आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए थे। उनके मन में यह भावना थी। उस समय वहाँ भरूच जिले में उस भीड़ में मुस्लिम बिरादरी के भी कुछ लोग थे। मैं सही कह रहा हूँ। आप का नाम लिख लीजिए- 'कावली गाँव, जम्बुसर तहसील, डिस्ट्रिक्ट- भरूच'। उसमें से एक मुस्लिम बिरादर ने आकर मुझे बताया कि पहली बार

हमें यह महसूस हो रहा है कि किसी को हमारी चिन्ता है। पहली बार ऐसा लग रहा है और पहली बार ऐसा शान्ति का माहौल हमने 10-15 सालों में यहाँ पर देखा है। उसमें खुश होने की ही बात है, गौरव की बात है। उसने यह कहा कि ये अंधियारे गलियारे जो पड़े थे, वहाँ एक सूरज निकला है। एक सदी पहले, दो सदी पहले एक नरेन्द्र नाम का सूर्य विलायत की भूमि पर जाकर, शिकागो की भूमि पर एक संदेश दे आया था, आज यहाँ एक दूसरा नरेन्द्र निकला है, जो पूरा सूर्य उदित हो चुका है। उस मुस्लिम बिरादर ने नरेन्द्र मोदी जी के लिए जो पंक्ति कही थी, उस पंक्ति को कह कर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। उसने कहा कि:

"है अगर हिम्मत तो अंधेरे में आकर मिला करो,
धूप में तो काँच भी चमका करते हैं।"

उसने कहा कि इस अंधियारे गलियारे को उजियारा करने के लिए आपकी सरकार ने जो काम किए हैं, हम उसकी सराहना करते हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने महामहिम जी के अभिभाषण पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(समाप्त)

SHRI NARENDRA KUMAR SWAIN (ODISHA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the President's Address. There are a number of programmes like Jan Dhan Yojana and Deen Dayal Antyodaya Yojana mentioned in the Address of the hon. President. This has

been circulated by the Centre to the States. First of all, I support the Motion of Thanks to the President's Address. The demonetization announced by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi has been supported by the entire people. They are happy because they live in villages. I know of my village wherein 85 per cent of people are daily wage workers. They earn their livelihood by working in the fields. They do not have land of their own. Much earlier, in the year 1982, land reforms were carried out there. So, small farmers have got land of only two acres by which they are earning their livelihood. I myself was a practising lawyer in the High Court. I had only two acres of land.

(Continued by 3B/KS)